

सचिन पायलट होंगे कांग्रेस का नया ओबीसी चेहरा

राहुल गांधी ने यह सोचा समझा निर्णय लिया, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद। इस निर्णय से बैकवर्ड, दलित व आदिवासी देश की राजनीति में अब पूरी तरह से सैंटर स्टेज पर आ गये हैं

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 मई। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का नया ओबीसी चेहरा हैं। राहुल गांधी ने बहुत सोच-विचार कर उन्हें, खासतौर से जातिगत जनगणना के संदर्भ में, पार्टी के नये ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जातिगत सर्वे ने पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र में पहुँचा दिया है।

आज शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग के बाद, सचिन पायलट और भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस के लिये उतारा गया। ये दोनों ही ओबीसी हैं। लेकिन चूँकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिये वे ईंडी की नज़र में हैं तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। बघेल का समय गुज़र चुका है।

सचिन पायलट युवा और करिश्माई नेता हैं। वे स्क्वड्र छवि के मालिक हैं तथा युवा एवं महिलाएं उनकी जबरदस्त प्रशंसक एवं समर्थक हैं। उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में ही नहीं,

■ सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के बाद, शाम को सचिन पायलट व भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करने के लिये उतारा कांग्रेस हाईकमान ने।

■ दोनों, नेता ओबीसी हैं। बघेल हालांकि वजनी हैं, क्योंकि, मु.मंत्री रह चुके हैं, परन्तु उन पर ईंडी का शिकंजा कसा हुआ है तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

■ अतः बघेल बीता हुआ, “पास्ट” (इतिहास) हैं। पर, पायलट युवा हैं, करिश्माई हैं तथा साफ व स्वच्छ छवि के नेता हैं, जिनकी युवाओं में, महिलाओं में, अच्छी लोकप्रियता है, केवल राजस्थान में ही नहीं, पर, उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी।

■ राहुल गांधी लगातार “जातिगत जनगणना” की बात कर रहे थे तथा ओबीसी, दलित व आदिवासी को पुनः कांग्रेस में लाने के लिये जातिगत नेताओं (कास्ट लीडर्स) को प्रोजैक्ट करने की ज़रूरत को पहचान रहे हैं।

अपितु पूरे उत्तर भारत में है।

अगर कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिये जोर लगाया होता, तो वे किसी भी पार्टी के प्रथम गुर्जर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आये होते और कांग्रेस

को उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा फायदा मिला होता, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों की बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाताओं का दबदबा है। वादे करना एक चीज है, किन्तु जाति-आधारित एजेंडे को वास्तव में और सही रूप में

कार्यान्वित करना बिल्कुल भिन्न चीज है।

चूँकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के महत्व और आवश्यकता के बारे में, तथा ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को कांग्रेस में वापस लाने की जरूरत के बारे में निरन्तर बात करते आ रहे हैं, इसलिये उन्होंने पिछड़ी जातियों के नेताओं को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अपेक्षानुरूप, सीडब्ल्यूसी मीटिंग मूलतः दो बिन्दुओं पर केंद्रित थी: पहलगाम हमला, जिसके विषय में एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री से कहा गया कि वे पाकिस्तान तथा उसके द्वारा पोषित आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। दूसरा बिन्दु जातिगत जनगणना थी, जिसके बारे में सरकार ने जो घोषणा की है, उससे कहीं बहुत ज्यादा कांग्रेस चाहती है।

कांग्रेस को आशंका है कि मोदी सरकार के अन्य जुमलों की तरह, जातिगत जनगणना भी कहीं एक जुमला बनकर न रह जाये। सीडब्ल्यूसी ने जो देकर कहा कि जातिगत सर्वे सही रूप में कार्यान्वित हो, जिससे यह सामाजिक सशक्तीकरण एवं परिवर्तन का एक प्रभावी उपाय बन सके।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के टेंडरों की जाँच के लिये आठ सप्ताह का समय

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बीते पाँच साल में दिए पांच सौ टेंडरों में भ्रष्टाचार की जाँच को लेकर जाँच एजेंसी को आठ सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका

■ विभाग के पाँच साल के पाँच सौ टेंडरों की जाँच के लिये गठित एसआईटी ने जाँच के लिये हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा।

पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी को 8 से 11 मई की अंतरिम जमानत मिली

जयपुर, 2 मई। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को, उनकी पत्नी के निधन के चलते, 8 से 11 मई तक अंतरिम जमानत का लाभ दिया है। जोशी को अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 11 मई को सुबह 8 बजे जेल में सरेंडर करना होगा। इससे पहले ईडी कोर्ट ने जोशी को गत 28 अप्रैल को पत्नी के अंतिम क्रिया- कर्म व धार्मिक रिवाजों के निर्वाह के लिए 4 दिन की अंतरिम

■ महेश जोशी के अधिवक्ता ने पत्नी के निधन के संबंध में रीति-रिवाजों के लिये अंतरिम जमानत 9 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

जमानत दी थी। इस अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला शुक्रवार पर रखा था। वहीं, अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार शाम को जोशी ने जेल में सरेंडर कर दिया था।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि महेश जोशी की उनकी पत्नी के निधन के बाद के रीति रिवाजों में हिस्सा लेना है। वे 71 साल के हैं और पत्नी के निधन के बाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हिमांशी तुम एक “परफैक्ट” फौजी वाइफ हो’

ले. विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल की पत्नी ललिता रामदास ने अभिनंदन किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 मई। भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल स्व. रामदास की पत्नी ललिता रामदास, जो एक शिक्षाविद् हैं, ने हिमांशी नरवाल की प्रशंसा की और कहा कि वे सही मायने में एक “फौजी की पत्नी” (परफैक्ट फौजी वाइफ) हैं, हिमांशी के पति लैफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे।

गुरुवार को विनय नरवाल का 27 वां जन्मदिन था। हिमांशी ने अपने दुःख और पीड़ा को दर्किनार रखकर शांति और सद्भावना की अपील कर गरिमा और परिपक्वता का परिचय दिया है। जिसका सोशल मीडिया पर कई दक्षिण पंथियों ने विरोध किया।

हिमांशी ने कहा, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए। लेकिन हम न्याय

■ जैसा कि विदित ही है, ले. विनय नरवाल गत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गये थे और हिमांशी शादी के दस दिन बाद ही विधवा हो गई थी।

■ गत गुरुवार को ले. नरवाल का 27वां जन्म दिन होता। उस दिन हिमांशी ने अपील की थी कि जो लोग ले. नरवाल के मौत का कारण बने, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये। पर, मैं नहीं चाहती कि हमें सभी मुसलमानों व कश्मीरियों पर गुस्सा निकालना चाहिये और उन्हें गालियाँ देनी चाहिये।

चाहते हैं। जिन लोगों ने विनय की हत्या की, उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी ने यह बात हरियाणा के करनाल में एक रक्तदान शिविर में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

ललिता रामदास ने एक नोट में लिखा कि हिमांशी, आप सही मायने में फौजी की पत्नी हैं, सेना, संविधान और

धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुकूल हैं। हिमांशी, जो अपनी शादी के 6 दिन बाद ही विधवा हो गई थी, को ललिता रामदास ने यह नोट लिखा। जाने-माने पत्रकार व लेखक परन्जॉय गुहा ठाकुरता ने यह पत्र सोशल मीडिया पर डाला है।

हिमांशी और विनय हनीमून के

लिए कश्मीर गए थे, क्योंकि यूरोप का वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। ललिता रामदास ने लिखा, “नौसेना अधिकारी की संभवतया सबसे उग्रदराज बेटी व पत्नी, जो आज भी जीवित है, की तरफ से नौसैनिक अधिकारियों की पत्नियों की जमात में शामिल सबसे युवा सदस्य को व्यक्तिगत टिप्पू है।” जातव्य है कि ललिता के पिता भी नेवी में एडमिरल थे।

ललिता ने लिखा, “मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं प्रैस से कहे गए आपके शब्दों की क्लिप बार-बार देखती हूँ। बाइस तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या के बाद, जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशान बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो आपकी असाधारण शक्ति, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई उल्लेखनीय है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पसमोदा मुस्लिम मूवमेंट, जो पिछड़े व दलित मुसलमानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है, को हाल ही में काफी बल मिला है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनैतिक रणनीतिकार मानते हैं कि मुस्लिम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विश्रंजम तो उनके मन में बसता है। केरल की राजधानी की अभूतपूर्व रूप से सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। विश्रिन्जम इन्टरनैशनल डीपवॉटर मल्टीपरवज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करने केरल की राजधानी में आये। यह 8900 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है।

यह देश का प्रथम कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में, “विकसित भारत” के स्वप्न के हिस्से के रूप में, क्रांतिकारी तरक्की का प्रतिनिधित्व करता है।

सामरिक महत्व वाले विश्रिन्जम पोर्ट की पहचान अत्यधिक प्राथमिकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हिमांशी तुम एक “परफैक्ट” फौजी वाइफ हो’

ले. विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल की पत्नी ललिता रामदास ने अभिनंदन किया

■ जैसा कि विदित ही है, ले. विनय नरवाल गत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गये थे और हिमांशी शादी के दस दिन बाद ही विधवा हो गई थी।

■ गत गुरुवार को ले. नरवाल का 27वां जन्म दिन होता। उस दिन हिमांशी ने अपील की थी कि जो लोग ले. नरवाल के मौत का कारण बने, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये। पर, मैं नहीं चाहती कि हमें सभी मुसलमानों व कश्मीरियों पर गुस्सा निकालना चाहिये और उन्हें गालियाँ देनी चाहिये।

चाहते हैं। जिन लोगों ने विनय की हत्या की, उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी ने यह बात हरियाणा के करनाल में एक रक्तदान शिविर में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

ललिता रामदास ने एक नोट में लिखा कि हिमांशी, आप सही मायने में फौजी की पत्नी हैं, सेना, संविधान और

लिए कश्मीर गए थे, क्योंकि यूरोप का वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। ललिता रामदास ने लिखा, “नौसेना अधिकारी की संभवतया सबसे उग्रदराज बेटी व पत्नी, जो आज भी जीवित है, की तरफ से नौसैनिक अधिकारियों की पत्नियों की जमात में शामिल सबसे युवा सदस्य को व्यक्तिगत टिप्पू है।” जातव्य है कि ललिता के पिता भी नेवी में एडमिरल थे।

ललिता ने लिखा, “मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं प्रैस से कहे गए आपके शब्दों की क्लिप बार-बार देखती हूँ। बाइस तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या के बाद, जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशान बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो आपकी असाधारण शक्ति, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई उल्लेखनीय है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पसमोदा मुस्लिम मूवमेंट, जो पिछड़े व दलित मुसलमानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है, को हाल ही में काफी बल मिला है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनैतिक रणनीतिकार मानते हैं कि मुस्लिम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ नैशनल हैरल्ड केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के निर्देश पर न्यायाधीश ने ये नोटिस जारी ? किए हैं।

अदालत में कार्यवाई के लिए नयी शिकायत दायर की थी। इसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाये गये हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम) ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये। यह मामला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असुरक्षित होटलों के संचालन पर रोक लगायें

राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर होटल अग्निकांड पर दिशा निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर के होटल में हुए अग्निकांड के बाद ऐसे असुरक्षित होटलों को बंद करने की मंशा जताई है। आयोग ने कहा कि अजमेर में रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन और नगर निगम सभी सरायों और होटलों की सूची बनाकर, उन्हें असुरक्षित पाए जाने पर, उनके संचालन पर रोक लगाए। इसके साथ ही, इन होटलों में फायर एनओसी की अनिवार्यता को लागू करें, ताकि यहां ठहरने वालों के साथ अग्निकांड जैसी जानलेवा घटना न हो। वहीं, आयोग ने अजमेर कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को कहा है कि शहर की सभी होटलों की सूची बनाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को कन्फर्म कर

राज्य सरकार व चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कार्यक्रम बनाये

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाए जाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा है कि वे चुनाव कार्यक्रम सहित बताएं

■ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 फरवरी तथा 25 मार्च 2025 के निर्देशों की पालना करने के लिये भी कहा।

कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। वहीं, राज्य सरकार को इस संबंध में 4 फरवरी 2025 व 25 मार्च 2025 को दिए गए निर्देशों की पालना के लिए कहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जस्टिस चन्द्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिराज सिंह देवदा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 30 मई को तय की है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ आयोग ने अजमेर कलैक्टर, एसपी तथा निगम आयुक्त को अजमेर के होटलों की सूची बनाकर सुरक्षा व्यवस्था की कन्फर्म रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इसकी रिपोर्ट आयोग में पेश की जाये और अग्निकांड में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देना सुनिश्चित किया जाये। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर दिए।

आयोग ने कहा कि अग्निकांड में जले होटल के मालिक ने स्थानीय प्रशासन से बिना फायर एनओसी लिए होटल संचालित की, जिसके चलते आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आग की लपटें देखकर होटल कर्मचारी भाग गए और

एक महिला को अपने बच्चे को बचाने के लिए होटल से नीचे फेंकना पड़ा। आयोग ने कहा कि शहर के कई आवासीय भवनों को होटलों में तब्दील किया जा चुका है और विभागों की स्वीकृति और एनओसी के बिना इनका संचालन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अचानक लिया गया यह निर्णय केवल सामाजिक न्याय व डेटा संग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्लिम आबादी, जिसको अनुमानित संख्या 25 मिलियन से अधिक है, को जाति और उपजाति के आधार पर विभाजित करने के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि इससे

हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसने हाल ही में संसद द्वारा पारित विवादास्पद वक्फ अधिनियम संशोधनों का विरोध करने में एकजुटता का प्रदर्शन किया था।

वरिष्ठ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार, जाति जनगणना का समय और उद्देश्य सरकार को व्यापक राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उनका तर्क है कि अचानक लिया गया यह निर्णय केवल सामाजिक न्याय व डेटा संग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्लिम आबादी, जिसकी अनुमानित संख्या 25 मिलियन से अधिक है, को जाति और उपजाति के आधार पर विभाजित करने के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि इससे

■ इन नेताओं के अनुसार, पूरे मुस्लिम समुदाय ने एकजुट व संगठित होकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया था, अब सरकार जातिगत जनगणना के जरिए मुसलमानों की एकता व एकजुटता को तोड़ना चाहती है।

■ इन मुस्लिम नेताओं के अनुसार, मुसलमानों में पसमंदा (बैकवर्ड) मुसलमान व अशरफ, अपर कास्ट जैसे सैय्यद, पठान, शेख आदि में विभाजन मौजूद है, पर, पूरे मुस्लिम समुदाय के हितों व समाज के “कम्युनिटी वेलफेयर” के कारण विभाजन सदा सुस्त रहते हैं, पर, अब जातिगत जनगणना, इस विभाजन (फॉल्ट लाइन) को और प्रज्ज्वलित करेगी।

उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है।

इस मुद्दे के मूल में, हाल ही में लागू किए गए वक्फ कानून को लेकर बढ़ता

तनाव है। यह कानून, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पुनर्गठित और केन्द्रीकृत करना था, को मुस्लिम नेताओं और अन्य लोगों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को विपक्ष की एकता पर आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि हिन्दू बहुल विपक्षी दलों ने भी कानून को चुनौती देने के लिए मुस्लिम नेतृत्व के साथ हाथ मिलाया। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस अप्रत्याशित गठबंधन का सामना करने के लिए मोदी सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा।

दिल्ली के एक राजनीतिक विश्लेषक, डॉ. इमरान कुरैशी का कहना है, “जाति गणना उतनी अनुकूल नहीं है, जितनी नज़र आती है। धार्मिक संबद्धता

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

रेटपेयर्स की सक्रिय भागीदारी से ही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

भले ही आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो व जीडीपी रैंकिंग में इस साल हम विश्व की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में हैं पर अर्थ व्यवस्था के तेजी से विकास के लिए रेटपेयर्स की भागीदारी बढ़ाने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फ्रीबीज के जमाने में केन्द्रीय वित्त सचिव अजय सेठ द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रेटपेयर्स को प्रोत्साहित करना जरूरी बताया है। दरअसल एक और राजनीतिक दलों द्वारा ऐन केन प्रकारेण सत्ता के स्वाद चखने की चाह पूरी करने के लिए लोकलुभावन फ्रीबीज सुविधाओं की घोषणाएं दर घोषणाएं की जा रही है तो दूसरी और देश को 2025 में जीडीपी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती सामने हैं। अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा गणित यह है कि एक तो करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कर के रुप में सीधे-सीधे आय सरकार को प्राप्त होती है तो दूसरी और सरकार अपनी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहुंचाने के लिए उधारी से काम चलाने वाली स्थिति होती है जिसे हम बजट प्रस्तावों में उधारी के रुप में देखते हैं तो तीसरा प्रमुख स्रोत रेटपेयर्स होते हैं। देश का सेविंग पूल इन्हीं से बनता है। अब जहां तक आयकर का प्रश्न है तो आधार और पेनकार्ड के चलते अब आयकर के दायरें से तो कोई बच भी नहीं सकता। खासतौर से नौकरीपेशा या निश्चित प्राण पाने वालों का तो आयकर सीधे-सीधे और बिना किसी छीजत के सरकार को प्राप्त हो ही जाता है। इसमें किसी तरह की चोरी की संभावना भी लगभग ना ही है। लगभग यही स्थिति जीएसटी के बाद देखने को मिल रही है और साल दर साल जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

दरअसल जब स्थानीय स्वशासन को परिकल्पना की गई थी तो उसके साथ यह भी था एक समय आते-आते यह संस्थाएं अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो जाएगी और इन संस्थाओं को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर एक और यह तो सपना ही बनकर रह गया दूसरी और राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का ऐसा चलन चलाया कि रेटपेयर्स की भूमिका कम से कम होती जा रही है। दरअसल रेटपेयर्स का प्रयोग सबसे पहले 1845 में माना जाता है। रेटपेयर्स की

रेटपेयर्स से सीधा सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरें में आती हैं। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरें में प्रमुखता से ला रही हैं। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

पर फ्रीबीज के दायरें में प्रमुखता से ला रही है। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

लोकतंत्र में समान अवसर और अधिकार रुप से पिछड़े लोगों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। संवेदनशील और लोकहितकारी सरकार के लिए यह आवश्यक भी हो जाता है। पर इसका मायना यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो राशि कर या अन्य रुप में प्राप्त की जाती है वह नहीं मिले और उसका भार भी ईमानदार कर दाताओं पर पड़े तो यह किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता है। फिर सरकार को सक्षम और कम सक्षम में कहीं ना कहीं अंतर करके ही चलना ही होगा। केन्द्रीय वित्त सचिव की मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि फ्रीबीज के कारण जो रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सहायता दी जाए पर इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि मुख्यधारा से वंचित के नाम पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोगों या परिवारों को भी यह सुविधाएं दी जाएं। इससे होता यह है कि जो आम करदाता है वह तो अपने आपको उगा मसूस करता ही है वहीं कहीं ना कहीं समाज में गेप भी बढ़ता है। इसके अलावा आर्थिक विकास में जो जनभागीदारी होनी चाहिए वह भी बाधित होती है। ऐसे में फ्रीबीज की राजनीति के बीच रेटपेयर्स की भागदारी को भी बढ़ाना ही होगा जिससे अर्थव्यवस्था का मल्टिपल विकास संभव हो सके। आज के लाभार्थियों को भी अर्थ व्यवस्था के व्यापक हित में समझना होगा।

–अमितिश सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, (वरिष्ठ लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शनिवार 3 मई, 2025

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, पुनर्वसु नक्षत्र दिन 12:34 तक, शूल योग रात्रि 1:41 तक, तैत्तिल करण प्रातः 7:52 तक, चन्द्रमा प्रतः 6:37 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेथ, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कंकर, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 12:34 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 7:52 से 2:02 तक है। आज गंगा सप्तमी और पूजन, गंगोत्पत्ति और चन्दन छठ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:29 से 9:07 तक, चर 12:24 से 2:02 तक, लाभ अमृत 2:02 से 5:18 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 6:56

 मेघ घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 सिंह घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।	 धनु चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नई है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।
 वृष परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	 कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	 मकर परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में चल रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
 मिथुन आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 तुला व्यावसायिक कार्यों को श्रायश्मिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 कुंभ स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 कर्क व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	 वृश्चिक नवीन कार्यों के संबंध में सरकारात्यक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 मीन व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

संपादकीय

तकनीकी युग में चुनाव आयोग में बड़े बदलावों और नवाचार की आवश्यकता है



सुनील दत्त गोयल

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान प्रदत्त है। लेकिन जब यह अधिकार गैर-नागरिकों यानी अवैध रूप से देश में दाखिल हुए घुसपैठियों को मिल जाए, तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। आज भारत इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है-विशेषकर सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह समस्या अधिक विकराल रूप ले चुकी है।

चुनाव आयोग को आधुनिकरण की जरूरत है। पिछले 15 वर्षों में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद जरूरी सुधारों और बदलावों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया है। हर चुनाव-चाहे लोकसभा हो या विधानसभा या ग्राम सभा-के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट होती है। यह समझ से परे है कि अब तक एक सामान्य वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई है जो सभी स्तरों के चुनावों के लिए मान्य हो। मेरा पहला सुझाव यही है कि एक सामान्य जनरल वोटर लिस्ट बनाई जाए। दूसरा अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिजन्स) को घर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आधार पर वोटिंग की सुविधा देने का ट्रायल शुरू किया है। यह सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर देश से बाहर रहने वाले नागरिकों, दूसरे राज्यों में रह रहे कामकाजी लोगों या छात्र-छात्राओं को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती? उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक या पोस्टल माध्यम से वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए।

मैंने स्वयं लासभग एक साल पहले अपना वोटर आईडी ऑनलाइन अपडेट किया था, लेकिन आज तक वह मुझे नहीं मिला। इससे यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? इसे समय से आगे की सोच अपनीानी होगी और तकनीकी रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा।

चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की सीमाएं : एक और बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनाती तो कर देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट (क्लेक्टर) और एसपी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। यह सही है कि आचार संहिता के समय वे आयोग के अंतर्गत होते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव प्रक्रिया में और गहराई तक की जाए, खासकर पोलिंग बूथ के अंदर।

अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जहां पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार के कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करते दिखते हैं। वोट किसے देना है, यह पूछते हैं और कई बार खुद वोट डाल देते हैं। यह अपने आप में एक नया 'बूथ कैम्पेनिंग' का तरीका है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल पोलिंग बूथ के अंदर तैनात हों और प्रत्येक वोटिंग प्रक्रिया पर निगरानी रखें। यहाँ हमारा यह सुझाव है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कहाँ और किस स्थान पर और कितनी होगी, यह भी चुनाव आयोग स्वयं अपने स्तर पर फैसला करें। तभी हम एक पारदर्शी और सुशुद्ध चुनाव प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं।

आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो : आज हमारे पास ई-आधार, मोबाइल, फेस आईडी और तमाम डिजिटल साधन मौजूद हैं। ऐसे में डाक द्वारा वोट भेजने की पुरानी प्रणाली को खत्म कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को विकसित करना चाहिए, ताकि जो लोग अपने गृह जनपद से बाहर हैं, वे भी आसानी से वोट डाल सकें। जैसे चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारी तथा सीमा पर लगे हुए सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों में वे सभी अधिकारी जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर होते हैं, वे पोस्टल बलेट का उपयोग करते हैं। वैसे ही आम नागरिकों को भी दो दिन पहले वोट डालने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलनी चाहिए। यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है।

स्थानीय कारकों को समझे चुनाव आयोग : चुनाव आयोग को चाहिए कि वह अपने जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह जानकारी अवश्य प्राप्त करे कि उनके जिलों में मतदान के दिन या उससे एक-दो दिन पहले अथवा बाद में कोई बड़ा त्योहार, विवाह

समारोह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजन तो नहीं है। यदि ऐसा कोई अवसर हो, तो ऐसी तारीखों से परहेज करते हुए वैकल्पिक मतदान तिथि का निर्धारण किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को समय से आगे सोचते हुए कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता, चाहे वह देश में हो या विदेश में, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।

चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: सिर्फ नागरिकों को ही मिले वोट देने का अधिकार

हाल ही में नियुक्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव सुधारों की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने देशभर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे वैश्विक लोकतंत्रों की चुनावी प्रणाली और राज्य-स्तरीय चुनाव नियमों का गहन अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन सदन में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई-ऑफिस और डिजिटल फाइल मैनेजमेंट को भी लागू किया गया है - जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सराहनीय प्रयास हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या ये प्रयास मतदाता पहचान की शुद्धता को भी सुनिश्चित कर पाएंगे? आज भारत के कई हिस्सों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध घुसपैठियों को वोटर आईडी जारी किए जा रहे हैं। इनमें से कई लोग न केवल मतदाता बन जाते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक में भी तब्दील हो जाते हैं।

दूसरा सवाल यह है कि इन दोनों चर्चाओं में आया है कि एक ही मतदाता के अलग-अलग जिलों में या शहरों में या राज्यों में कई वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इन डुप्लीकेट सिस्टम को जितनी शीघ्रता से चुनाव आयोग हटाएगा, उतना ही देश की सुरक्षा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए फायदेमंद होगा।

पश्चिम बंगाल: जन सांख्यिकीय बदलाव का जीवंत उदाहरण : पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दशकों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा से सटी जमीन पर हजारों लोग बगैर वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं और स्थानीय राजनैतिक समर्थन और ढीली प्रशासनिक जांच के कारण आसानी से भारतीय मतदाता बन जाते हैं। यह जनसांख्यिकीय बदलाव न केवल स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और कानून-व्यवस्था को

प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गहराई से नुकसान पहुंचाता है। कई पूर्व अधिकारियों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल के सीमावर्ती जिलों में कुछ जगहों पर स्थानीय जनसंख्या में गैर-नागरिकों का अनुपात 25-30 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

वोटर आईडी के लिए नागरिकता सत्यापन क्यों है जरूरी?

आज की प्रणाली में नाम, पता और उम्र के आधार पर वोटर आईडी मिल जाता है। कोई ठोस नागरिकता प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या नागरिकता पंजीकरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं है। नतीजतन, फर्जी पहचान पत्र बनाकर अवैध घुसपैठिये भी मतदाता बन जाते हैं।

इस घातक खामी को दूर करने के लिए नियम उपाय अत्यंत आवश्यक हैं:

1. सी.पी.न और पुराने वोटर आईडी को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ा जाए : जिस तरह असम में प्रक्रिया अपनाई गई, उसे तकनीकी रूप से दुरुस्त कर अब पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

2. आधार, पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र से वोटर आईडी की क्रॉस वेरिफिकेशन: आधार की बायोमेट्रिक जानकारी और पासपोर्ट की राष्ट्रीयता आधारित पुष्टि का उपयोग कर मतदाता पंजीकरण को अधिक सख्त बनाया जाए।

3. डिजिटल जियो-टैग वेरिफिकेशन टीमें का गठन: हर मतदाता के पते का ऑन-ट्राउंड डिजिटल सत्यापन किया जाए, जिससे फर्जी पते पर वोटर आईडी लेना मुश्किल हो।

4. फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सख्त सजा का प्रावधान:

फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी लाभ लेने या वोटर आईडी बनवाने पर कानूनी कार्रवाई हो और तुरंत आईडी निरस्त किया जाए। एक राष्ट्र, एक चुनाव तभी संभव जब एक समान नागरिक पहचान सुनिश्चित हो

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की यह पहल कि पूरे देश में एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए - ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक - एक दूरदर्शी योजना है। लेकिन जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि इस सूची में केवल भारतीय नागरिक शामिल हों, तब तक यह प्रयास अधूरा और भ्रामक होगा। राज्यों के बीच नियमों की असमानता, स्थानीय दबाव, भ्रष्टाचार और तकनीकी कमजोरियाँ

अजमेर डिस्कॉम ने समग्र राजस्व आवश्यकता तैरिफ एवं निवेश योजना पर प्रैजैंटेशन दिया

अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में ऑडियो-विजुअल प्रैजैंटेशन के माध्यम से जानकारी दी

अजमेर, (कासें)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष विद्युत अभियोग 2003 की धारा 62 एवं 64 के अंतर्गत समग्र राजस्व आवश्यकता टैरिफ निर्धारण एवं निवेश योजना की स्वीकृति याचिका प्रस्तुत की गई है। शुक्रवार को टैरिफ निर्धारण को लेकर पंचशील स्थित अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को जानकारी दी गई।

अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पी वर्मा ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए याचिका के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ऊर्जा शुल्क (एनर्जी चार्जेंज) में कमी का प्रस्ताव किया गया है, जबकि सीमित रूप में फिक्स्ड चार्जेंज में वृद्धि की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परिवर्तन से लगभग 99 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें एनर्जी चार्ज में छूट का लाभ मिलेगा।

घरेलू टेरिफ संख्या 9 व अघरेलू टेरिफ 16 से घटाकर 11

■ **उद्योग, कंज्यूमर राइट संगठन के प्रतिनिधि ने भाग लिया आमजन 13 मई तक आपत्तियां व सुझाव दर्ज करा सकेंगे**

किया :- वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए घरेलू टैरिफ स्लैब की संख्या को 16 से घटाकर 9 तथा अघरेलू टैरिफ स्लैब की संख्या को 15 से घटाकर 11 कर दिया गया है, जिससे

उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की गणना एवं समझना सरल हो सकेगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के उपरांत उसे आमजन तक पहुंचाया जाना होता है। आमजन द्वारा दिए गए सुझावों पर डिस्कॉम गंभीरता से विचार करेगा। प्रेजेंटेशन कार्यक्रमाला में निदेशक तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी, मुख्य अभियंता एमएल मीणा, मुख्य अभियंता राजीव वर्मा, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, कंज्यूमर राइट्स संगठनों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं सहित अन्य संबंधित

हितधारक एवं अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी हितधारकों ने डिस्कॉम की पारदर्शिता एवं उपभोक्ता हित में उठाए गए कदमों की सराहना की।

13 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां व सुझाव :- निगम द्वारा प्रस्तुत याचिका की प्रतियां आम नागरिकों के अवलोकन हेतु अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय तथा निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आमजन अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव निर्धारित प्रारूप में 13 मई तक प्रेषित कर सकते हैं।

विकसित और विश्व गुरु भारत बनाने में नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण : राज्यपाल बागड़े

■ **गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ**

लेकिन एक महर्षि ने कहा कि यह सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि आचरण नहीं होगा तो इनका दुरुपयोग ही होगा। बागड़े ने कहा कि हमें मन बनाना होगा और मन को बनाने की विधाओं में नये उदाहरण, नई तकनीक और जज्बा महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने पूरे मन, दृष्टि और व्यवहार से विद्यार्थियों को ज्ञान दें क्योंकि एक विद्यार्थी शिक्षक के आचरण को देखकर ही उसी आचरण को अपनाता है। उन्होंने कहा कि चेतना, गुणवत्ता और जवाबदेही के भाव हममें जगने होंगे। राज्यपाल ने प्रेरित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद दो शिक्षा नीति अस्तित्व में आई लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में सनातन मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ युगीन आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम है। हमारे राज्य की सशक्त

परम्परा रही है जहां ईला न देणी आपणी हालरियो हुलराय द्वारा जहां मैं अपनी कोख से ही देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का पाठ सीखाती है वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत तत्त्व जवाबदेही सभी का उद्देश्य होना चाहिए तभी नाया भारत, सशक्त भारत और समर्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे।

मुख्य वक्ता और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृति एवं विद्यार्थी ने कहा कि किसी भी देश की नींव उसकी शिक्षा पद्धति होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीयता से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि आत्म प्रेमोत्पन्न, अनुभूति, एकत्व अनुभूति केवल सिद्धांत नहीं अपितु व्यवहार का विषय और परम ध्येय होना चाहिए। अतिथि देवो भव के कारण हमने सदियों से अनेक जातियों और कबीलों को शरण दी भले ही हमने अनेक दुष्परिणाम झेले

लेकिन हमारी अतिथि परम्परा आज भी मूल्य रूप में जीवंत है। तकनीकी सत्र की की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि सर्वोच्च क्रिया और शोध का सर्वे, अध्ययन हम करते नहीं और शोध जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज उच्च शिक्षा के मानक बदलने की आवश्यकता है हमें हमारी योग्यता, क्षमता और बोध पर संकोच और अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। कबीले आते गए और हिन्दोस्तान बना गया हमारी संस्कृति और धाती की महत्ता और शक्तिमत्ता ही है कि हम अपने सामर्थ्य से देश और समाज की ओगे बढ़ते जा रहे हैं। आज शिक्षा नीति अंतर्गत आवश्यकता है कि विज्ञान, टेक्नोलोजी और डिजिटल क्षेत्र में भी अपने मूल विषयों और मूल्यों को छोड़े बिना भी विकास को प्राप्त हो सकते हैं। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय की संकल्पना और प्राप्ति रिपोर्ट कुलपति प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने प्रस्तुत की।

सत्र में विषय प्रतिपादन न्यास के जयपुर प्राप्त अध्यक्ष प्रो राजीव सक्सेना ने किया।

राज्यपाल ने इस अवसर कैम्पस की गुलाब वाटिका और जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया और पूर्व में अपने द्वारा रोपे गए पौधे की जानकारी ली। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम किया गया और कार्यक्रमों में औपचारिक रूप से अमूमन किए जा रहे प्लास्टिक प्रयोग को पूरी तरह खत्म किया गया। अतिथि सत्कार में भी अतिथियों को तुलसी एवं अन्य उपयोगी पौधे प्रदान किये गये। आयोजन सचिव डॉ. राजीव सक्सेना ने प्रस्तावना पेश की एवं आभार कुलसचिव डॉ. अभिषेक गोयल ने मनाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, उपखंड अधिकारी रजनी माधवाल, पूर्व सांसद कनकलम काठार, पूर्व राज्यमंत्री धनसिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, रामचरूप महाराज सहित जनप्रतिनिधि-अधिकारी मौजूद रहे।

सरकार की मंशा है कि गांवों के प्रतिभावान खिलाड़ी भी खेलों में आगे आएं : मेघवाल

बीकानेर, (कासं)। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत को वर्ष 2०47 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने में खेलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मेघवाल शुक्रवार को डॉ करणी सिंह स्टेडियम में नवनिर्मित मल्टी पर्पज इनडोर हॉल के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम फिट तो इंडिया फिट तथा खेलो इंडिया का नारा दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। सरकार की मंशा है कि शहरी क्षेत्र के साथ गांवों के प्रतिभावान खिलाड़ी भी आगे आएं तथा खेलों के मानचित्र पर भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम दुनियां की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

प्रधानमंत्री की मंशा है कि हम भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनें। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें उद्यम शिक्षा और चिकित्सा के साथ खेलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बने इस इनडोर हॉल का अधिकतम उपयोग खेलों के लिए किया जाए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शहरी क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को यह इनडोर स्टेडियम दिखाया जाए जिससे उनमें खेलों के प्रति रुचि पैदा हो। उन्होंने शहर की कॉलोनियों के सार्वजनिक उद्यानों में खेलों की सुविधाएं विकसित

■ कटौती से पूर्व इन टंकियों को जलापूर्ति लाइन से जोड़ दिया गया होता तो इतनी समस्या नहीं होती

एक सप्ताह में 3 और दूसरे सप्ताह में 3 नई टंकियों को जलापूर्ति लाइन से जोड़ दिया जायेगा जिससे पुरानी टंकियों का भार कम होगा। नहरबंदी को 1० दिन बीतने को है लेकिन अब तक जोड़ा नहीं गया।

पीएचईडी को 21 से 27 अप्रैल के बीच धरणीधर, स्टेडियम और नयाशहर में बनी नई टंकियों को शुरू करना था। इससे नत्थूसर टंकी का भी भार कम होता। नहीं जोड़े जाने के कारण इस टंकी के टेल इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। एक दिन छोड़कर आ रहे पानी के बाद

भी टेंटोंयां सूखी हैं। इससे लोगों का गुस्सा फूट गया। नत्थूसर टंकी पहुंच गए। वहां चल रही सप्लाई बंद करा दी। इस बीच शोभासर से भी पानी बंद हो गया। बाद में जेईएन बबीता ने समझाकर लोगों को वापस एक बजे पानी देने का वादा किया तब जाकर लोग शांत हुए। शहर में करीब 28 टेल इलाके हैं। टेल यानी वो इलाके जो टंकी का सबसे अंतिम छोर होता है। अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते पानी का फ्लो कम हो जाता है। खेमचंद सिंगारिया,एसई पीएचईडी बीकानेर का कहना है कि करणीसिंह स्टेडियम टंकी तो बनकर तैयार है। मिलान का काम चल रहा है। अभी मौजूदा टंकियों पर ही सप्लाई को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं। सप्लाई लाइन से जोड़ा भी जा रहा है। नत्थूसर इलाके में लाइट जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में सप्लाई में दिक्कत हुई।उनकी दिक्कत को दूर कर दिया गया है।

स्काउट-गाइड ने परिंडे लगाए

नोखा, (कासं)। यहां राजकीय मांगोलाल बागड़ी महाविद्यालय में पक्षियों के लिए विशेष पहल की गई है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए महाविद्यालय प्रांगण में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सत्यनारायण राजपुरोहित ने इस पहल की जानकारी दी। स्काउट एंड गाइड प्रभारी सुमित्रा देवल के मार्गदर्शन में यह कार्य किया गया। इस अभियान में महाविद्यालय के रैजर्स और रोवर्स ने उत्साह से भाग लिया। रोवर्स में पवन छीपा, अजय गोदारा, पंकज बिश्नोई, चुन्नीलाल, पूनमचंवं हुड्डा और रामदेव उपाध्याय ने सक्रिय भूमिका निभाई। रेंजर्स में सपना छीपा, कपिश खाली और दिशा पिलानियां ने प्रमुख योगदान दिया। छात्रों को अपने घरों के आसपास भी परिंडे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।



केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगाशहर का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक जेतानंद व्यास भी मौजूद थे।

जेतानंद व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के

आसपास बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। यह स्वास्थ्य केन्द्र इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सुमन छाजेड़ ने कहा कि अस्पताल का शुभारंभ गंगाशहर क्षेत्र के लिए नई शुरूआत है। उन्होंने कहा कि केन्द्र पर

पी.एच.डी. प्रवेश काउंसलिंग

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा वेटरनरी महाा विद्यालया, बाँ बागाने र, पी.जी.आई.वी.ई.आर., जयपुर, वेटरनरी महाविद्यालय, नवानियां (उदयपुर) में अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग 2 मई को वेटरनरी कॉलेज बीकानेर के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई।

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष प्रो. हेमंत दाधीच ने बताया कि तीनों महाविद्यालयों में 4० अभ्यर्थियों को आई.सी.ए.आर. द्वारा आयोजित आई.सी.ए.आर. –ए.आई.सी.ई. (पी.एच.डी) में प्राप्त स्कोर के आधार पर प्रमाण पत्र जांच कर पीएच.डी. की सीटों पर प्रवेश दिया गया। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन प्रो. राजेश धृडिया, निदेशक पी.एम.ई. प्रो. उर्मिला पानु, निदेशक क्लीनिक्स प्रो. प्रवीण बिस्नोई, परीक्षा नियंत्रक प्रो. मनीषा माथुर मौजूद थे।

श्रीगंगानगर में बदला मौसम, तेज आंधी के साथ बारिश

श्रीगंगानगर, (कासं)। मई महीने की शुरूआत के साथ ही जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देर रात से जिले के कई क्षेत्रों में तेज आंधी और हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया जिससे तापमान में 1० से 15 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आमजन को तेज गर्मी से राहत मिली है।

श्रीगंगानगर शहर सहित पदमपुर, रायसिंहनगर, जैतसर और सूरतगढ़ क्षेत्र में रात करीब 12 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर हवाओं की गति 6० से 7० किमी प्रति घंटा तक रही। इसके कारण सड़कों पर पेड़ गिर गए, विद्युत पोल टूट गए और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति

■ केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी

आपूर्ति विभाग के उपायुक्त महावीर प्रसाद व्यास ने शुक्रवार को पंचायत समिति सभाकक्ष में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान में लक्ष्यनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसलिए इस अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब समस्त उचित मूल्य दुकानदारों से अपेक्षा है कि इसे अभियान में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें जिससे ऐसे अपात्र लाभार्थी जो योजनानुसार पात्रता की सीमा में नहीं होने के बावजूद राशन का गेहूं उठाकर वास्तविक लाभार्थी का हक छीन रहे हैं, उन्हें हटाया जा सके। उपायुक्त महावीर प्रसाद व्यास ने कहा कि ऐसे अपात्र व्यक्तियों को तुरंत अपनी पात्रता रद्द करवा लेनी चाहिए अन्यथा अभियान समाप्त के बाद अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त महावीर प्रसाद व्यास तथा जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बैठक में उचित मूल्य दुकानदारों की समस्याएं सुनी और यथासंभव मौके पर ही समाधान भी किए।

लालगढ़ रेलवे स्टेशन से पांच माह की बच्ची चोरी

बीकानेर, (कासं)। लालगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर से एक 5 माह की बच्ची को चुरा ले जाने का मामला सामने आया है। टैक्समी में सवार होकर आए महिला-पुरुष पर बच्ची को चुरा ले जाने का शक है और जीआरपी पुलिस दोनों को फ्लौदी में तलाश रही है।

बज्जू निवासी सुरेश भोपा का परिवार 29 मार्च को दोपहर देन से बीकानेर आया और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के तीन नंबर प्लेटफार्म के पास डेरा जमाया था। सुरेश, उसकी पत्नी सुनीता 3० अप्रैल की शाम को कचरा बीनने गए थे। डेरे में सुरेश की छोटी बहन 8 साल की पुष्पा, बेटियां 3 साल लाल्हा और 5 माह की अंजली ही थीं। इस दौरान टैक्समी में सवार एक महिला और पुरुष वहां पहुंचे और 5 माह की अंजली को चुरा ले गए। उस समय अन्य दोनों बच्चियां सो रही थीं। पति-पतिन रात को 9.3० बजे वापस लौटे तो अंजली नहीं मिली तो उसकी खोजबीन

श्रीगंगानगर में बदला मौसम, तेज आंधी के साथ बारिश

■ श्रीगंगानगर शहर सहित पदमपुर, रायसिंहनगर, जैतसर और सूरतगढ़ क्षेत्र में रात करीब 12 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई

बाधित हो गई। सूरतगढ़, पदमपुर, अनुपगढ़ और घडुसावा सहित अनेक स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने तथा बंगाल की खाड़ी से

आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। मंगले एक सप्ताह तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। 5० से 6० किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है।

■ इस स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक बाल रोग विशेषज्ञ नियुक्त किया

सभी आवश्यक सुविधाएं और संसाधन मुहैया करवाने के प्रयास किए जायेंगे। सीएमएचओ डॉ पुखराज साध ने बताया कि तीस बेंड के अस्पताल से गंगाशहर, भीनासर, गोपेश्वर बस्ती, गोगंगेट और शिव वैली सहित आसपास के लोगों को सहूलियत होगी। इस स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक बाल रोग विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। वहीं दंत रोग विशेषज्ञ जल्दी ही लगाया जायेगा। इसके अलावा तीन चिकित्सा अधिकारी, छह नर्सिंग कर्मी तथा एक-एक फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन भी लगाए गए हैं।

हिस्ट्रीशीटर गुरजंट सिंह का पैदल जुलूस निकाला

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले में अपराध नियंत्रण के तहत पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर गुरजंट सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे एसपी कार्यालय से सेंट्रल जेल तक पैदल जुलूस में ले जाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे समाज में अपराध के प्रति सख्त संदेश जाए।

गुरजंट सिंह के खिलाफ 18 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले हैं। उसकी गिरफ्तारी चूनाबढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें अमित, श्रवण, गोपी और सीडीआर सेल के मंगतराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारत में हिस्ट्रीशीटर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड लम्बा होता है और जो समाज के लिए खतरा माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने 'हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट' जैसे कानून लागू किए हैं। उदाहरण स्वरूप, राजस्थान में 'राजस्थान हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, 1९53' के तहत ऐसे अपराधियों की सूची बनाई जाती है और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है।पुलिस को ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने, उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और समय-समय पर उनकी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने और समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की जाती है।

लालगढ़ रेलवे स्टेशन से पांच माह की बच्ची चोरी

■ टैक्समी में सवार होकर आए महिला-पुरुष पर बच्ची को चुरा ले जाने का शक है ■ जीआरपी पुलिस दोनों को फ्लौदी में तलाश रही है

की। देर रात को सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस हरकत में आई और बच्ची की खोजबीन शुरू की गई। सीसीटीवी फुलाले और छानबीन की तो पता चला कि टैक्समी में सवार महिला-पुरुष लालगढ़ से श्रीगंगानगर चौराहे पहुंचे थे और वहां से बस में बैठकर फ्लौदी की तरफ गए हैं।जीआरपीएसएचओ आनंद गिला के नेतृत्व में टीम फ्लौदी गई है और बच्ची और उस उठा ले जाने वालों की तलाश की जा रही है।



बीकानेर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक को केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने संबोधित किया।

बीकानेर, (कासं)। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आज बीकानेर हवाई अड्डा परिसर में समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की अध्यक्षता में रखी गई है। समिति सदस्य पंकज अग्रवाल ने बताया कि इस बैठक में खानूवाला विधायक विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल, समिति के सदस्य पंकज अग्रवाल, गुमान सिंह राजपुरोहित, संपत पारीक, अशोक मीणा, महेन्द्र बोथरा सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक से पूर्व आमजन से सुझाव लिए गए थे उन पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति सदस्यों ने अपने विचार रखे किस तरह बीकानेर बेहतर हवाई सेवा दी जा सके और उनका विस्तार कैसे हो उस पर विस्तार से चर्चा हुई। केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि आज जो सुझाव मिले हैं, उनसे नाल एयरपोर्ट विस्तार होगा जिससे और अधिक हवाई सेवाएं मिलेंगी जिसमें बीकानेर से कोलकाता, सूरत, मुंबई कनेक्टिंग सेवाएं मिलेंगी। बीकानेर नाल हवाई अड्डे से बीकानेर शहर तक बस चलेगी जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शहर की विभिन्न दर्शनीय स्थलों की बुकलेट दी जायेगी। नाल हवाई अड्डे की मैन रोड चौड़ी कर सीन्दीयकरण किया जायेगा।

पीबीएम में 21 बड़े कूलर भेंट

बीकानेर, (कासं)। जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वाराकप्रसाद पचींसिया ने बताया कि गर्मी अपने पूरे परवान पर है और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में रहने को मजबूर है लेकिन जो रोगी है उनको अस्पताल में इलाज के लिए जाना ही पड़ेगा। अस्पतालों में पड़ रही गर्मी से निजात दिलाने हेतु बीकानेर जिला उद्योग संघ की अनुशंसा पर भामाशह जयचंद लाल ढागा ने अपने ट्रस्ट राजदेवी जयचंद लाल ढागा ट्रस्ट के माध्यम से पीबीएम अस्पताल में 21 बड़े कूलर अधीक्षक डॉ सुरेंद्र वर्मा को भेंट किये ताकि मरीजों व उनके परिजनो को इस भयंकर गर्मी से राहत प्रदान की जा सके। पीबीएम अधीक्षक सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस बार बीकानेर लगातार हीट वेव की चपेट में रहा है जिससे स्थस्थ व्यक्ति भी बीमार हुआ जा रहा है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। रोगियों की व्यथा को समझते हुए भामाशह जयचंद लाल ढागा ने मरीजों व साथ आए परिजनों को शीतल दवा उपलब्ध करवाने हेतु 21 बड़े कूलर भेंट किये गए हैं । राजदेवी जयचंद लाल ढागा चेरिटेबल ट्रस्ट के जयचंद लाल ढागा ने बताया कि इस बार गर्मी ने ईसान, पशु पक्षी सबका हाल बेहाल कर रखा है और ऐसी तपती गर्मी में पीबीएम में भर्ती रोगियों को अगर गर्मी से निजात मिलती है तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस अवसर पर दन्त रोग विशेषज्ञ डॉ जितेंद्र आचार्य उपस्थित हुए।

बीकानेर में आंधी तूफान का अलर्ट

बीकानेर, (कासं)। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान तो कम होगा लेकिन अंधड़ और बारिश से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पचास से साठ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 मई को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य से ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। आज एक बार पुनः जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ बारिश व तेज आंधी (हवा की गति 5०-6० किमी.) दर्ज होने की प्रबल संभावना है। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघगर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के कई भागों में जारी रहने की प्रबल संभावना है। आज अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री गिरावट होने तथा हीटवेब से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।राजस्थान में आगामी एक सप्ताह हीट वेव की संभावना नहीं है। बीते चौबीस घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को तापमान में कुछ कमी आई है। आने वाले कुछ दिनों तक पारा कम होगा लेकिन चालीस डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा।

आनंदम स्थल में प्याऊ का शुभारंभ

बीकानेर, (कासं)। कर्मवान फाउंडेशन द्वारा पीबीएम अस्पताल परिसर के आनंदम विश्राम स्थल में प्याऊ का शुभारंभ शुक्रवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी व व्यापार मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने किया। कर्मवान फाउंडेशन अध्यक्ष वेद व्यास ने बताया कि गर्मी के महेनजर प्रतिबंध इस प्याऊ का संचालन किया जाता है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गुंजन सोनी ने घस नैक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए किया गया यह कार्य अत्यधिक उपयोगी है। यह कार्य अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। व्यापार मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने कहा कि कर्मवान फाउंडेशन सेवा कार्यों में सदैव अग्रणी रहती है।

सी डैक

CDAC

प्रदेश अधिसूचना

उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग और इसके अनुप्रयोग पर सी-डैक उन्नत स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (कोई भी लिंग), महिला (कोई भी श्रेणी), ईड्यूकेयूसर, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए

प्रकाश डाला गया

• अवधि: 6 महीने

• मोड: ऑफलाइन (भौतिक)

• कोई पंजीकरण शुल्क नहीं

• कोर्स फीस: ₹.1,75,000

मुक्त

फ़ायदे

• उद्योग विशेषज्ञ मार्गदर्शन

• सी-डैक विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन

• केवल एससी/एसटी/ईड्यूकेयूसर/महिलाओं को 10,000/- का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा।

• नवीनतम प्रौद्योगिकी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई, 2025

c-huk@cdac.in

https://c-huk.cdacb.in

CBC 06140/12/0002/2526

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, तीन जने घायल

ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर सुबह करीब चार बजे हुआ हादसा, पुलिस मौके पर पहुंची

पाली, (नि.सं)। पाली जिले में शुक्रवार की सुबह सुमेरपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने चार लोगों की मौत और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई है। यह दर्दनाक घटना ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर सुबह करीब चार बजे हुई। जब एक तेज रफ्तार इनोवा कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से पीछे से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी लोग डायलाना कलां के रहने वाले थे। इनमें दो भाइयों का परिवार शामिल था, जो मुंबई से सुमेरपुर के पास एक सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में सुरेश रावल की पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दूसरे भाई विष्णु के पुत्र उत्तमजी रावल ने अस्पताल में इलाज के दौरान



हादसे में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

दम तोड़ दिया। हादसे में कुल चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से हर्षिता (18) को जोधपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा अनीता और दिया

का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार चला रही युवती को एयरबैग खुलने से मामूली चोटें आईं और उनकी जान बच गई। पुलिस आशंका को कब्जे में लेकर सुमेरपुर अस्पताल की मोचरी में रखवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे

कि इनोवा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए, जिसे बाद में क्रेन की मदद से हटाया गया। सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर सुमेरपुर अस्पताल की मोचरी में रखवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे

■ कार में सवार सभी लोग डायलाना कलां के रहने वाले थे, इनमें दो भाइयों का परिवार शामिल था

■ परिवार के लोग मुंबई से सुमेरपुर के पास एक सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव जा रहे थे

■ बताया जा रहा है कि कार चला रही युवती को एयरबैग खुलने से मामूली चोटें आईं और उसकी जान बच गई

के कारणों को विस्तृत जांच कर रही है। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

गिरिजा व्यास की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन

उदयपुर, (कासं)। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास की पार्थिव देह शुक्रवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गई। शाम पांच बजे अशोक नगर स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अशोक नगर मोक्षधाम में उनके भतीजे विवेक शर्मा ने मुखानि दी। अंतिम संस्कार वैदिक विधि से हुआ, इसमें 104 वेद मंत्र पढ़े गए। कांग्रेस नेत्री की अंतिम यात्रा में सैकड़ों कांग्रेसकर्ता एवं विशिष्ठ जन शामिल हुए।

जानकारी के अनुसार डॉ. गिरिजा व्यास 31 मार्च को घर पर गणगौर का पूजन कर रही थीं। दीपक के कारण उनकी चुनौ में आग लग गई थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनकी संपाला था। उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहां से उनकी अहमदाबाद रेफर किया था। 90 प्रतिशत झुलसने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि पहले उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था लेकिन दो दिनों से तबीयत फिर बिगड़ गई थी। 79 वर्षीय गिरिजा व्यास ने शुक्रवार शाम करीब 7.15 बजे अहमदाबाद स्थित जायडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। देर रात उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई गई थी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

■ वैदिक विधि से हुआ अंतिम संस्कार, भतीजे ने मुखानि दी

और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दैत्य मगरी स्थित निवास पर पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास के पार्थिव शरीर पर कांग्रेस का ध्वज एवं पुष्प चक्र अर्पित किये। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में राजस्थान सरकार के पूर्व अध्यक्ष धर्मरत्न सिंह राठीड़,संदीप चौधरी,प्रवन गोदारा,उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व कलेक्टर तारा चंद मीणा,पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, बसंती मीणा भी शामिल थे। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजसमन्द विधायक दीप्ती किरण माहेश्वरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठीड़ आदि ने भी दैत्य मगरी स्थित निवास पर पहुंच कर पुष्पांजलि अर्पित की। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने दिवंगत कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास के निधन पर दुःख प्रकट किया।

टेम्पो सवार परिवार सुंधा माता के दर्शन कर सोनाणा खेतलाजी जा रहा था

पाली, (नि.सं)। पाली में कार और टेम्पो की जोरदार टक्कर में पिता और बेटी की मौत हो गई। वहीं तीन साल के मासूम समेत आठ लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रानी हॉस्पिटल से पाली, सुमेरपुर रेफर किया गया। पाली से 3 साल के मासूम को देर रात को जोधपुर रेफर किया। हादसा

■ फॉक्स वैगन कार से एक परिवार चारभुजा से चाणोद जा रहा था, रानी और केनपुरा के बीच हादसा हुआ



हादये में हुये घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया।

घायलों का पाली, सुमेरपुर व रानी में इलाज जारी इस हादसे में टेम्पो में सवार जालोर जिले के देरदरी निवासी फुसराम (55) पुत्र रामाराम प्रजापत और उनकी बेटी कविता (25) पत्नी देवाराम की मौत हो गई। जिनकी बाँड़ी रानी हॉस्पिटल की मॉच्यूरी में रखवाई

गई है। हादसे में 8-9 जने घायल हुए हैं। पांच घायलों को पाली लाया गया, जहां से 3 साल के मासूम कार्तिक पुत्र देवाराम को जोधपुर रेफर किया गया। जालोर जिले के देलदरी हॉल अहमदाबाद निवासी पुनीत (14) पुत्र फुसराम प्रजापत, कोकिला (50)

पत्नी फुसराम, पाली जिले के चाणोद हाल मुंबई निवासी जगदीश पुत्र पुखाराम और उनके बेटे मनोज (25) का पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। शेष तीन घायलों का सुमेरपुर और रानी में उपचार चल रहा है।

पहलगाम आतंकी हमला : सुरक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर

अजमेर पुलिस ने 300 से अधिक संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया

अजमेर, (कासं)। गत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आतंरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार से मिले निर्देश पर राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में रह रहे संदिग्धों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर जिला पुलिस शहर में रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंया घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार सुबह पांच बजे से सचं अभियान चलाते हुए क्रिश्चयनगंज थाना और हरिभाऊ उपाध्याय नगर

■ पुलिस के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारतीय नहीं पाई जाती है तो संबंधित विभागों के माध्यम से उसे वापस उसके देश भेजा जाएगा

थाना क्षेत्र के कई इलाकों से करीब 300 से अधिक संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिड़ और सीओ नॉर्थ रूद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व

पुलिस टीम ने करीब 300 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां पुलिस पृष्ठताछ के साथ उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारतीय नहीं पाई जाती है तो संबंधित विभागों के माध्यम से उसे वापस उसके देश भेजा जाएगा। दस्तावेजों की पुष्टि के लिए संबंधित विभागों को भी मौके पर बुलाया गया है। अभियान में करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे।

ट्रेन में महिला का बैग चोरी

फुलेरा, (नि.सं)। सवारी गाड़ी संख्या 14701 गंगानगर-बांड़ा ट्रेन में बदमाशों ने महिला के लाखों के गहने से भरा बैग चोरी कर ले गए। महिला फुलेरा से किशनगढ़ जा रही थी। तभी फुलेरा जीआरपी थाना इलाके में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पति की शिकायत पर फुलेरा जीआरपी थाने पर केस दर्ज हुआ है। प्रारूप जानकारी अनुसार फुलेरा की मिश्र कॉलोनी निवासी गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि मेरी पत्नी विजय लक्ष्मी गौड़ एवं बेटी विधि शेखावत, वैभव शेखावत 29 अप्रैल को प्रातः 9.40 बजे शादी समारोह में जाने के लिए फुलेरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 14701 के आगे के जनरल कोच में बैठकर किशनगढ़ जा रही थी। उनके पास बड़ा लेडीजर्स पर्स था। जिसमें एक छोटा पर्स था। जिसमें सोने की ज्वेलरी थी। जिसको रास्ते में नेरना रेलवे स्टेशन के पास देखा तो नहीं मिला।

रिजिष्ठ्र सहायक भर्ती प्रक्रिया बीकानेर से शिफ्ट

शिक्षा विभाग जयपुर के स्कूल में डॉक्ट्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा

बीकानेर, (नि.सं)। प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा वैसे तो बीकानेर के पास है, लेकिन ज्यादातर काम यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। अब शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए डॉक्ट्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी बीकानेर के बजाय जयपुर के एक सरकारी स्कूल में होगा। इसके लिए निदेशालय से एक टीम जयपुर जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी आदेश में कहा गया है कि लिपिक ग्रेड सेकेंड व कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 24 का रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने

जारी कर दिया है। इसमें चयनित कैंडिडेट्स के डॉक्ट्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 14 मई से 28 मई के बीच जयपुर के महामा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 में किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स को लिस्ट में शामिल किया गया है, उन्हें अपने ऑरिजनल डॉक्ट्यूमेंट्स के साथ पहुंचना होगा। सभी कैंडिडेट्स को रोल नंबर के आधार पर अलग अलग तारीखों में आमंत्रित किया जा रहा है। कैंडिडेट्स को शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर

सक्षम अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना है। इनकी दो-दो प्रतियां साथ में संलग्न करनी है और स्व प्रमाणित भी करनी है। कैंडिडेट्स को अपना ई-आधार भी पेश करना होगा, जिसमें क्युआर कोड हो। निर्धारित शपथ पत्र भी पेश करने होंगे। अब कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि ये काम बीकानेर में क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्ट्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निदेशालय में लंबी चौड़ी कर्मचारियों की टीम है। इसके बाद भी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में ये काम किया जा रहा है। इससे निदेशालय कमजोर हो रहा है।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी डिटैन

■ लड़की की तबीयत बिगड़ने पर पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया

डिलीवरी बाँय उसे अपनी बाइक पर बैठाकर दोस्त के घर ले गया। आरोप है कि वहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी मौके से फरार हो गया। लड़की अपने घर पहुंची और मां को घटना बताई। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवा दिया जहां चिकित्सकों ने उसका

इलाज शुरू किया। इतला मिलने पर देर रात को बीछवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की के बयान नहीं हो सके। सुबह पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए। घटनाक्रम का मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएचओ धीरेन्द्रसिंह शेखावत ने बताया कि पोक्सो एक्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी जांच सीओ सिटी श्रवणदास कर रहे। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज जाएंगे। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता की आरोपी डिलीवरी बाँय से 6-7 माह से जान पहचान थी।

कार्यालय नगर परिषद बून्दी

क्रमांक:- 574-79 दिनांक:- 30.04.2025
-:: निविदा सूचना ::-
नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी निविदा सं०: विधुत /2025-26 /558 दिनांक 30/04/2025 की निविदा दिनांक 01/05/2025 से दिनांक 12/05/2025 शाय: 6.00 बजे तक ऑनलाईन विक्रेय की जायेगी। निविदा दिनांक 13/05/2025 को 3.00 बजे तक प्राचा की जायेगी तथा निविदा दिनांक 13/05/2025 को 04.00 बजे ऑनलाईन खोली जायेगी।। विस्तृत शर्त व विवरण निविदा sppp.rajjasthan.gov.in पर eproc.rajjasthan.gov.in पर DLB2526SLR0B03191 तथा कार्यालय समय मे किसी भी कार्यदिवस को नगर परिषद मे देखा जा सकता है।
राज.संवाद/सी/25/1631 आयुक्त नगर परिषद, बून्दी

कृषि महाविद्यालय बीकानेर
[स्वामी केसवानन्द राजस्थान कृषि विविद्यालय]
क्रमांक :- कृष्/लेखा शाखा/निविदा/2025/140 दिनांक :- 02/05/2025
ई-बोली सूचना संख्या 03/2025-26
एसकेआरयू परिसर एवं महाविद्यालय के 02 कार्य किन्दुओं पर सफाई कार्य जॉब बेसिस आधार पर करवाये जाने हेतु श्रम विभाग से पंजीकृत सेवा प्रदाय एजेंसियों से आमंत्रित बोली (टेंडरी बिड पद्धति) में इच्छुक बोलीदाता दिनांक 02.05.2025 से 14.05.2025 सांय 06:00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण शर्त व पूर्ण विवरण वेब साईट www.dipronline.org <http://sppp.rajjasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाईट <http://raubikaner.org> पर देखी जा सकती है। अत्यु्कालीन ई-बोली की अनुमति लागत 11.00 लाख है।। NIB Code: SKA2526A0007, UBN Code: SKA2526SLR0B00015
राज.संवाद/सी/25/1670 अयुक्ता

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, उत्तर
नगर निगम नग, नोर्टेडिफिक कोडिज एरियर, डेडिडेजि डेड, जोधपुर. 342004
फोन नं. :- 0291-2651464, ईमेल :- najdhjodhpur@gmail.com
क्रमांक :- विकास/उत्तर/निविदा/2025-26/846 दिनांक :- 01/05/2025

ई-निविदा सूचना संख्या
नगर निगम जोधपुर की ओर से विभिन्न विकास कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की विस्तृत जानकारी एवं शर्त इत्यादि वेबसाईट <http://eproc.rajjasthan.gov.in>, www.sppp.raj.nic.in एवं जोधपुर नगर निगम उत्तर की वेबसाईट <https://lsg.rajjasthan.gov.in/mcjin> देखी जा सकती है।
UBN No. : DLB2526WSO803359
राज.संवाद/सी/25/1652 महापौर आयुक्त

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर
सिटी जुबली हॉल के पास, नगर परिषद रोड, धौलपुर
Mail : dhoulpur.w@rajjasthan.gov.in, Ph: 05642-223349
खुली बोली आमंत्रण सूचना
इस कार्यालय के लिए पंचाघाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र योजना अन्तर्गत महिला केन्द्र प्रबंधक, महिला परामर्शदाता, आई टी, वर्कर एवं बहुउद्देशीय सहायक के पदो के लिए अस्थाई आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विनिर्दिष्ट संवेदक/संस्थाओं से दिनांक 06.05.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती है एवं ई निविदा की अनुमानिक लागत 14.70 लाख है। बोली आमंत्रण सूचना/निविदा प्रप्रत्य शर्त व आवश्यक दस्तावेज अंगीहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में <http://sppp.rajjasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
UBN No.-WMP2526SLRC00019, NIB No.-WMP2526A0019
(जय प्रकाश) सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, धौलपुर

Office Of Superintending Engineer
PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 04/2025-26 Item No. 1-A to 1-H
Bids for Annual Rate contract for Construction & commissioning of 100 mm dia tube wells with submersible pump sets etc. complete work in all types of strata & laying, jointing, testing, commissioning of HDPE pipe line including defect liability period of 01 year at PANCHAYAT SAMITI AKLERA of PHED Division Jhalawar District Jhalawar (With Material Complete) are invited from interested bidders upto 05.05.2025 at 18.00 Hours Other particulars of the bid may be visited on the www.dipr.rajjasthan.gov.in, <http://rajwatar.gov.in>, <http://eproc.rajjasthan.gov.in>.
Departmental websites <http://sppp.rajjasthan.gov.in> and
NIB No. PHE2526A0617
UBN No. PHE2526WSOB01462, PHE2526WSOB01464, PHE2526WSOB01466, PHE2526WSOB01467, PHE2526WSOB01469, PHE2526WSOB01471, PHE2526WSOB01472, PHE2526WSOB01474
Superintending Engineer
PHED Circle Jhalawar

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर

क्रमांक-333/सांचौर/निविदा/25/109 दिनांक-17/04/2025
निविदा सूचना संख्या 01/2025-26
NIB No. : 2526A0177
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर Building Repair हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिष्ठत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/काछा एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रु. 74.79 लाख है।
निविदा आवेदन 21 अप्रेल 2025, 9.30 बजे से 05 मई, 2025, सांय 6.00 बजे तक
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट <http://dipr.rajjasthan.gov.in> व <http://sppp.rajjasthan.gov.in> व <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कर्तव्य दू. बी.एन. संख्या निम्नानुसार है।
UBN No.-1. UBNPNW544, 2. UBNPNW545, 3. UBNPNW546, 4. UBNPNW547
5. UBNPNW548, 6. UBNPNW549
(प्रदीप पंवार)
अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सांचौर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर
क्रमांक-333/सांचौर/निविदा/25/109 दिनांक-17/04/2025
निविदा सूचना संख्या 01/2025-26
NIB No. : 2526A0177
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर Building Repair हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिष्ठत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/काछा एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रु. 74.79 लाख है।
निविदा आवेदन 21 अप्रेल 2025, 9.30 बजे से 05 मई, 2025, सांय 6.00 बजे तक
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट <http://dipr.rajjasthan.gov.in> व <http://sppp.rajjasthan.gov.in> व <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कर्तव्य दू. बी.एन. संख्या निम्नानुसार है।
UBN No.-1. UBNPNW544, 2. UBNPNW545, 3. UBNPNW546, 4. UBNPNW547
5. UBNPNW548, 6. UBNPNW549
(प्रदीप पंवार)
अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सांचौर

राजस्थान स्टेट मॉर्नस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(नक्सल एलएन का उद्योग) लुकरा (एन.डी.डी. कोड: 330015, राजस्थान) 9413300435, ईमेल: luckybhargava.rsmml@rajjasthan.gov.in
दिनांक :- 02/05/2025

संशोधित निविदा सूचना
निविदा संख्या एवं दिनांक कार्य का विवरण
E-Tender No. 14/23-24 Dated 24.03.2025 सफाई इस्त्रोलेसन, डैरिंटिंग एण्ड कॉमिशनिंग ऑफ 3 मोल, 145 केवी, एनएफ 6 रॉकिट ब्रेकर अनुमानित राशि रु. 1378000/- लाख, धरोहर राशि रु. 27800/-, निविदा शुल्क रु. 1180/- प्रोसेसिंग फीस 1000/-
Due date extended up to 21.05.2025 UBN No. MMJ2425GL0B00234
E-Tender No. 15/23-24 Dated 24.03.2025 सफाई इस्त्रोलेसन, डैरिंटिंग एण्ड कॉमिशनिंग ऑफ स्टेप ऑय ट्रान्सफॉर्मर, 630 केवीए एण्ड सफाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर 100 कोवॉल अनुमानित राशि रु. 2000000/- लाख, धरोहर राशि रु. 40000/-, निविदा शुल्क रु. 1180/- प्रोसेसिंग फीस 1000/-
Due date extended up to 21.05.2025 UBN No. MMJ2425GL0B00235
E-Tender No. 16/23-24 Dated 24.03.2025 रेत कोर्रुप्ट कोर ट्रान्सफॉर्मेशन वर्क ऑफ सल्फ्यूर एसिड फ़ैक्ट्री एच जेड एल. चॉट ड्र ड्रामकोटडा माहेश्वर, आरवारणामुण्डल, उदयपुर अनुमानित राशि रु. 1000000/- लाख, धरोहर राशि रु. 20000/-, निविदा शुल्क रु. 1180/- प्रोसेसिंग फीस 1000/-
Due date extended up to 21.05.2025 UBN No. MMJ2425GL0B00236
विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com, www.sppp.rajjasthan.gov.in अथवा जनरल मैनेजर (एन.एम.), से सम्पर्क करें।
राज.संवाद/सी/25/1639 अय महानिदेशक (का.वर्ष प्रशा.)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(टी डब्ल्यू एलएन), नया एलए हाउस एरियर, हेवी इंडस्ट्रीज एरिया, जोधपुर- 342003
दूरभाष : 0291-2742336 फैक्स : 0291-2745259

अल्कालिक ई-निविदा सूचना
जोधपुर डिस्कॉम में निम्नलिखित कार्य के लिए अत्यकालिक तकनीकी, वाणिज्यिक और मूल्य ई-बोली आमंत्रित की जाती है-
निविदा संख्या कार्य का विवरण ज्यूरी एन नंबर
टीएन 765/400 केबी जीएसएस सांवता के अंतर्गत पावरग्रिड के अस्थापी पंचाडीय कनेक्शन हेतु 11 केबी लाइन 33 केबी इस्त्रोलेसन (9.5 किमी) ओपन लाइन-1.5 किमी यूबी केबल पर 1,11,0/4 केबी 01 नंबर 315 केबीएस-स्टेशन, और, 11 केबी वे के कार्य हेतु टैन्कर्ट ऑफ आधुनिक, निर्माण, परीक्षण और कामगारिण के कार्य हेतु अत्यकालिक निविदा आमंत्रित की जाती है।
अन्य विवरण जैसे निविदा मूल्य धरोहर राशि, निविदा प्रस्तुत करने / खुलने की तिथि का विवरण इत्यादि वेबसाईट www.energy.rajjasthan.gov.in/jdvnnl एवं <http://eproc.rajjasthan.gov.in> द्वारा जानी जा सकती हैं। निविदा कर्ताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन www.eproc.rajjasthan.gov.in पर निविदा डाउनले से पहले निविदा दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें से।
सूचना :- अभियंता के निर्देशों से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन, तिथि बढ़ने की जानकारी आदि केवल वेबसाईट www.energy.rajjasthan.gov.in/jdvnnl, www.sppp.rajjasthan.gov.in पर <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध करायी जायेगी।
राज.संवाद/सी/25/1629 अधीक्षण अभियन्ता (टीडब्ल्यू)

किसी संवेदी विवरणों के लिए टेली फोन नंबर 1800 1800 6045

राष्ट्र निर्माण में पब्लिक सर्वेंट की अहम भूमिका : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान कर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया है कि वे सभी अमृत काल के योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान देंगे तथा उ्कृष्ट लोक सेवा के माध्यम से हमेशा राजस्थान का नाम देशभर में रोशन करेंगे। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष से चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की पहल की है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली यह परीक्षा पास करके प्रदेश के युवाओं ने अपने माता-पिता के साथ ही क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के बाद जीवन में बेहतर कार्य करते हुए परिजनों की खुशी के भाव को जीवन में आगे भी बनाएं रखें।

मुख्यमंत्री ने ‘कर्ता के आगे हारे करता’ उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा दृढ़ संकल्प के साथ की गई मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता के बाद भी चयनित युवाओं के जीवन में नए परिश्रम का दौर शुरू होगा। क्योंकि राष्ट्र निर्माण और गरीब



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उनके निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया।

कल्याण में लोक सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने जीवन में विनम्रता एवं धैर्य को अपनाते हुए आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने का आ न किया।शर्मा ने कहा कि लोक सेवक प्रशासन के कर्णधार हैं तथा लोक सेवा का महत्व हमारे समाज और राष्ट्र के लिए असीमित है। इसलिए लोक

सेवकों का नवाचारी होना महत्वपूर्ण है, ताकि आम लोगों को बेहतर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने आ न किया कि हमारे प्रदेश की मिट्टी ने हमेशा से वीरों, विद्वानों और कर्मठ लोगों को जन्म दिया है और अब वे सभी भी अपनी सेवा के माध्यम से गौरवमयी मिट्टी की खुशबू को फैलाएं और

कर्मभूमि के साथ ही जन्मभूमि से जुड़े रहे।

समारोह में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की इस पहल से प्रदेश के होनहारों को प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसेवक के रूप में देश और

भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा आज

जयपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से शनिवार को शाम साढ़े पांच बजे जलेब चौक से गाजेबाजे और लवाजमे के साथ भगवान श्री परशुराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। ब्रह्म पीठाधीश्वर रामरतनदास देवाचार्य, शुक्ल संप्रदायाचार्य अलबेली शरण माधुरी एवं अन्य शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे। मुख्य रथ के आगे 2100 महिलाएं एक ही गणवेश में मंगलगान करते हुए शोभायात्रा की भव्यता में चार चांद लगाएंगी। शोभायात्रा में विभिन्न स्वरूपों की जीवंत एवं स्वचालित 21 झांकियां होंगी।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन का लाभ देने को कहा है।

न्यायमित्र पूर्वी माधुर ने बताया कि याचिकाकर्ता 63 साल की एकल बुजुर्ग महिला है और मानसिक दिव्यांग है। उसके पिता सचिवालय और मां चिकित्सा विभाग में कार्यरत थीं। दोनों का पूर्व में निधन होने पर वह अपने भाई-भाभी के पास रहने लगीं। वहीं कुछ सालों पहले उसकी भाभी का भी निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने फैमिली पेंशन के लिए पिता के विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पिता ने सरकारी सेवा में रहते हुए कभी भी याचिकाकर्ता की मानसिक दिव्यांगता के बारे में कोई काय्मक विभाग ने जुलाई, 2010 को उसे यह पेंशन देने से इनकार कर दिया।

31 जिला संयोजक एवं सह-संयोजक नियुक्त

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान में जन जागरूकता के लिए प्रदेश के 31 जिलों में संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की है।

अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन जागरूकता के लिए जिला संयोजकों एवं सह-संयोजकों की नियुक्ति की गई है।

सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन

जयपुर। भारत सरकार के निर्देश पर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक ग्राम स्तर पर 1 मई से 31 मई तक 30 दिवसीय सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत योजनान्तर्गत लाभ से वंचित पात्र कुषकों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। इन सेचुरेशन कैम्प्यों में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र के संचालक एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के समन्वयक उपस्थित रहेंगे। ऐसे कुषक जो कि योजना की पात्रता रखते हैं परन्तु योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके आवेदन सीएससी केन्द्रों पर सेचुरेशन कैम्पेन के दौरान पूर्ण करवाये जायेंगे।

गंभीर चोट आई और भय का माहौल पैदा हो गया। इसी तरह पूर्व में भी यहां घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा मोती ढुंगरी सेटेलाइट अस्पताल में भी बिना जरनेटर बिजली जाने पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने की खबर प्रकाशित हुई है। इस तरह की भविष्य में घटनाएं नहीं हो, इसलिए मामले में प्रसंज्ञान लेकर एसएमएस अस्पताल और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं।

समय आने पर मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूँगा। आशा बैरवा व डॉ. अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिये मैं सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने के लिये तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि धरना प्रदर्शन के कारण आत्महत्या के उत्तेरण जैसा आरोप न्यायालय में नहीं टिकेगा और ऐसे अनर्गल अनुसंधान नतीजे देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर प्रशासनिक कार्यवाही होगी। सत्य की जीत होगी तथा मैं एक बार पुनः निर्दोष साबित होऊँगा।

■ मुख्यमंत्री ने युवा-अधिकारियों से विमर्शता व धैर्य को अपनाने तथा जहाँ से जुड़े रहने का किया आह्वांन

समाज की सेवा का सौभाग्य चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता है। महानिदेशक पुलिस ने कहा कि अपने सेवाकाल में हमेशा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दें और अपनी सफलता में माता-पिता और परिजनों के योगदान को कभी नहीं भूलें।

समारोह में जयपुर निवासी दृष्टिबाधित मनु गर्ग ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए बताया कि उन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में 91वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का मूल मंत्र अपनी माताजी के संकल्प को बताया। वहीं देशभर में 20वां स्थान हासिल करने वाले जोधपुर निवासी त्रिलोक सिंह ने बताया कि लोक सेवक के रूप में वे भारतीय सेना में सेवा दे चुके अपने पिता द्वारा दी गई प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चयनित प्रतिभाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री के साथ चयनित युवाओं का सामूहिक फोटो सेशन भी हुआ। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे।

दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लोगो और थीम साँन्ग लांच किया

जयपुर। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ‘बाल विवाह मुक्त राजस्थान’ अभियान की शुरुआत की है।

उपमुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम साँन्ग भी जारी किया गया है। यह लोगो और साँन्ग लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित

अंता विधायक मीणा को मिली सजा रद्द करने से इनकार

■ हाईकोर्ट ने तत्काल सरंंडर करने के आदेश दिये

प्रकरण दर्ज थे अभियुक्त के भय व आतंक के कारण पुलिसकर्मी व लोक सेवक उसके खिलाफ बयान देने की स्थिति में नहीं थे। यहां तक की पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद रिपोर्ट तक नहीं की गई। वहीं अभियुक्त के स्थानीय इलाके में मौजूद होने के बावजूद तीन साल तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इससे पुलिस की लाचारी साफ नजर आती है। इसके अलावा तत्कालीन प्रशिक्षु आईपीएस व तहसीलदार ने अभियुक्त के खिलाफ बयान दिए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त विधायक की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले के अनुसार अकलेरा के तत्कालीन एसडीओ रामनिवास मेहता ने 5 फरवरी, 2005 को स्थानीय कलेक्टर को पत्र लिखा कि 3 फरवरी को मनोहर थाना के पास गांव के लोक खाताखेडी के उपसरपंच के चुनाव का रिपोल कराने को लेकर रास्ता रोक रहे थे। इस दौरान वह

और प्रशिक्षु आईपीएस सहित अन्य स्टाफ समझाइश कर रहा था इतने में कंवरलाल अपने साथियों के साथ वहां आया और उसके सिर पर रिवाजस्वर लगाकर दोमिनट में रिपोल की घोषणा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसने विभाग की ओर से कराई गई वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़कर जला दी। घटना के समय दो थानाधिकारी व एक आरपीएस भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। कलेक्टर की ओर से इस पत्र को

दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लोगो और थीम साँन्ग लांच किया

■ बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें

करेगा। इस लांचन के साथ, राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभियान के तहत सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप

रांका ने बताया कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य

एसपी को भेजने के बाद 9 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वहीं बाद में निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीजेएम, मनोहर थाना ने 2 अप्रैल, 2018 को कंवरलाल को बरी कर दिया।

इसके खिलाफ परिवादी और राज्य सरकार की अपील पर एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने 14 दिसंबर, 2020 को कंवरलाल को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ पेश रिवीजन पर हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा गत 17 अप्रैल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विधायकी रद्द करने की मांग

जयपुर। विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा को विरुद्ध एग्रेड ज्वालावाड द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को यथावत रखा गया है।

राजस्थान प्रेक्ष कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोट्यासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा को सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं

मानसिक दिव्यांग अविवाहित पुत्री को फैमिली पेंशन देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पूर्व राजकीय कर्मचारी की मानसिक रूप से दिव्यांग 62 साल की अविवाहित पुत्री को अंतरिम रूप से फैमिली पेंशन अदा करे। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग पेंशन का लाभ दें और इसकी गणना फैमिली पेंशन में नहीं की जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना के संबंध में भी जानकारी पेश करने को कहा है। अदालत ने मामले में राज्य बिधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को कहा है कि वह प्रकरण में याचिकाकर्ता को सभी जरूरी सहायता मुहैया कराए, ताकि उसे फैमिली पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल सके। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से याचिकाकर्ता के जीवन स्तर को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता 62 साल की महिला है और मानसिक दिव्यांग होकर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं सहित अन्य शारीरिक बीमारियों से ग्रसित है। वह अपने रिटायर भाई के साथ रहती है और उनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र स्रोत भी नहीं है। दूसरी ओर अदालत के सामने आया की यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की किसी भी आयु की संतान मानसिक दिव्यांग या शारीरिक दिव्यांग होकर जीविकोपार्जन में असमर्थ है तो उसे आजीवन फैमिली पेंशन दी जाएगी। इसके बावजूद महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति

योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है।

अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए अन्तिम तिथि 28 मई निधारित की गई है।

एसएमएस और सेटेलाइट अस्पताल के हालातों पर लिया प्रसंज्ञान

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हाँस्पिटल की छत का प्लास्टर गिरने और मोती ढुंगरी सेटेलाइट अस्पताल में संसंधी के अभाव पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही आयोग ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और जिला कलेक्टर से दोनों अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त कर रोगियों की सुरक्षा व सुचारु इलाज सुनिश्चित कर

मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने यह आदेश इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर दिए। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने कहा कि अस्पताल जनमानस को रोग से मुक्ति दिलाने का पवित्र स्थान है, न कि यहां आए रोगियों को जोखिम में डालने की जगह। एसएमएस अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरने से यहां भर्ती दो मरीजों को

कांग्रेस सरकार ने पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग कर झूठा फंसाया : गोठवाल

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में मेने गरीब, दलित व वंचित लोगो को न्याय दिलाने के लिए धरने किये थे। मेरी आवाज को बंद करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुलिस मशिनरी का दुरुपयोग करके मुझे लालसोट केस में झूठा फसाया है।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश लिखकर मुझे जमानत प्रदान की थी। जिस आदेश के विरुद्ध राजस्थान की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई।

मगर उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मैं गिरफ्तारी के समय से ही लगातार न्याय की मांग करता आ रहा हूँ। पुलिस ने मेरे द्वारा दिये गये अग्रिम तथ्यों के आधार पर मुझे अपनी जाँच में पूरी तरह से निर्दोष माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूर्ववती पुलिस रिपोर्ट व नई पुलिस रिपोर्ट दोनों को विचारित करने के पश्चात् न्या आदेश पारित करने के निर्देश दिये है।

उन्होंने कहा कि मुझे न्याय पालिका पे पूर्ण विश्वास है। जो भी कोई राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी मेरे पीछे लगे है वो

इस केस की आड में मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। मेरी गिराह में मृतक सुप्रता आशा बैरवा तथा मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा दोनों को न्याय नहीं मिला बल्कि दोनों कांग्रेस सरकार के निर्देश अनुसंधान के शिकार हुये। प्रकरण में लालसोट के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों द्वारा डॉ. अर्चना शर्मा को प्रताड़ित किये जाने और उनसे भारी धन राशि मांगे जाने की महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर आई है, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने षड्यंत्रपूर्वक दबा दिया था,

जयपुर। भारत सरकार के निर्देश पर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक ग्राम स्तर पर 1 मई से 31 मई तक 30 दिवसीय सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत योजनान्तर्गत लाभ से वंचित पात्र कुषकों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। इन सेचुरेशन कैम्प्यों में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र के संचालक एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के समन्वयक उपस्थित रहेंगे। ऐसे कुषक जो कि योजना की पात्रता रखते हैं परन्तु योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके आवेदन सीएससी केन्द्रों पर सेचुरेशन कैम्पेन के दौरान पूर्ण करवाये जायेंगे।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने सिविल लाईंस कूच करने का ऐलान किया है। अगर सरकार ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में प्रदेशभर से एक लाख नौजवान जयपुर आएंगे और रैली कर शहर को जाम कर देंगे। उन्होंने कहा, वे एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने, रीट लेवल-1 और आरएएस भर्ती की जांच करवाने की मांग को लेकर युवा

सात दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा, एसओजी की जांच में सामने आया है कि 400 से ज्यादा एसआई फर्जी तरीके से चयनित हुए हैं। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार

चुप है। उन्होंने इस पूरे मामले में भाजपा-कांग्रेस पर मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा, कि अपनी सरकार के समय सचिन पायलट ने युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पैदल यात्रा निकाली थी, लेकिन अब वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने मंत्री डॉ किरीटीलाल मीना को लेकर

कहा कि वे मंत्री बनने के बाद युवाओं की आवाज नहीं उठा पा रहे। हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार और बेनीवाल समर्थक वापस सहीद स्मारक पर इकठ्ठा हुए और धरना जारी रखा।

आमजन को हीट वेव से राहत देने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लू-तापघात (हीट वेव) और गर्मी जनित अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे और जिला कलक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का पूर्ण रख-रखाव किया जाए एवं किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को बिजली, पानी एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पूरे समर्पण भाव से काम करें, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारी की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में लू से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की हर समय उपलब्धता हो। हीट वेव की स्थिति में नियमित निगरानी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लू-तापघात और गर्मी जनित अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी रखें।

रखी जाए तथा चिकित्सालयों में हर समय सभी आवश्यक मेडिकल

व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में

- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलैक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।**

संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों में इस वर्ष तक प्रमुख 12 सेवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन्हें अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, एम्बुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। शर्मा ने कहा कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संधारित करने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति की न केवल आभा आईडी बनाई जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आभा आईडी का अधिक से अधिक उपयोग शीघ्र प्रारम्भ हो।

इस दौरान, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नवाचारों का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए उप वायु सेना प्रमुख

नई दिल्ली, 02 मई। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को नए उप वायु सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल एस.पी. धरकर का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल तिवारी गांधीनगर स्थित दक्षिण-

- उन्हें 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल एस.पी. धारकर की जगह नियुक्त किया गया है।**

पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नवाचारों का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

भारतीय वायु सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने 2 मई 2025 को उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है।

पाक प्रधानमंत्री का यू ट्यूब अकाउण्ट भारत में बैन

नई दिल्ली, 02 मई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया। चैनल पर अब यह संदेश दिखा रहा है- 'यह सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी आदेशों के कारण इस देश में उपलब्ध नहीं है।'

शहबाज शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई-प्रोफाइल खाता है, जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक किया है। इससे

श्रीनगर के हिन्दू परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी

पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर के उक्त हिन्दू परिवार को पाकिस्तान निर्वासित किये जाने की तैयारी है

- परिवार ने कोर्ट में अपील की थी कि उसने बहुत पहले अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सँरक्ष कर दिया था। उनके पास सभी वैध भारतीय दस्तावेज हैं और वो भारतीय हैं।**

हिरासत में लिया गया, जबकि उनमें से एक ने बहुत पहले ही अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सँरक्ष दिया था और भारत में बस गया था।

परिवा का प्रतिनिधित्व करने

के बाद कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता-परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से

परिवार ने कोर्ट में अपील की थी कि उसने बहुत पहले अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सँरक्ष कर दिया था। उनके पास सभी वैध भारतीय दस्तावेज हैं और वो भारतीय हैं।

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर वियतनाम पहुंचे

ये पवित्र अवशेष वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के रुप में 2 मई से 21 मई तक वियतनाम के विभिन्न भागों में प्रदर्शित किए जाएंगे

नयी दिल्ली/ हो चीमिन सिटी, 02 मई। भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश, मिश्रों और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह शहर पहुंचे है।

ये पवित्र अवशेष 02 मई से 21 मई तक वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में वियतनाम में लोगों के दर्शन के लिए विभिन्न पवित्र स्थलों पर रखे जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रिजिजू ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों की ओर से एक सार्थक संदेश दिया। उन्होंने वियतनाम बौद्ध

पवित्र अवशेषों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंच के सहयोग से प्रदर्शित किया जा रहा है। इन्हें 07 मई तक हो ची मिन्ह शहर में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा,

उसके बाद 21 मई तक ताई निन्ह, हनोई और हा नाम में प्रदर्शित किया जाएगा।

पवित्र अवशेषों को आज एक भव्य सार्वजनिक शोभा यात्रा के माध्यम से थान ताम पैगोडा लाया गया, जहाँ उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।

इस उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनी और भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका शामिल है, जो भारत-वियतनाम बौद्ध विरासत की गहरी जड़ों को प्रदर्शित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी है।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि साल 2019 में डीओआईटी के तत्कालीन अधिकारी के

पाक अधिकृत कश्मीर के 1००0 मदरसे बंद

समझा जाता है कि भारतीय सेना के हमले की आशंका में यह कदम उठाया गया है

- इसी बीच पाकिस्तान ने भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर खोलने की घोषणा की।**

छिपे बैठे आतंकवादियों को खत्म किया था। यह कार्रवाई 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला करने के दस दिन बाद हुई थी। हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सरकार के निर्देशानुसार 1०00 से अधिक मदरसे बंद कर दिए गए हैं। उन्हें कम से कम 1० दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों के लिए छा्ट्रियों की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को गिलगित

नैशनल हैरल्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अखबार नेशनल हैरल्ड, उसके सहयोगी पत्र-पत्रिकाओं और उसकी संघटियों की स्वामी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड (एजेएल) का यंग इंडियन ड्राइव लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहण किये जाने में कथित धांधली पर आधारित है। इस सौदे से कुछ समय पूर्व वाईआईएल का गठन किया गया था जिसकी अधिकांश हिस्सेदारी कांग्रेस के दोनो शीर्ष नेताओं राहुल व सोनिया के पास है। ईंडी 2०14 से इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया।

निर्देश देते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, "इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह आदेश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है।" हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारतीय नागरिक होने के बावजूद पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने कहा जब तक ऐसा स्थापन पुरा नहीं हो जाता और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई निर्वासन या अन्य बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने मामले को बंद कर दिया और परिवार के दावों को सत्यापित करने का काम अधिकारियों पर छोड़ दिया।

राज्य सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग, पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते।

समय पर चुनाव कराया जाना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। नगर पालिका चुनाव का मामला अलग और नया है, जबकि पंचायत चुनाव वाले मामले में अदालत राज्य सरकार व चुनाव आयोग से चुनाव कार्यक्रम मांग चुकी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 30 मई को तय की है।

मार्ग, मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हव्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुरा फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आद्य भैन रोड आयड, उदयपुरा फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जाजोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्टीयल एरिया, फैस प्रथम, जालौरा फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

